सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-33 अंक-4 | 21 फरवरी से 7 मार्च 2018 | मुख्य संपादक कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ 8 | मूल्य : 2 रुपये

पीएनबी घोटाले पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट)

नीरव मोदी व उसके सहयोगियों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक से की गई धोखाधड़ी लोगों पर एक घातक आर्थिक हमला

इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जोरदार जनआन्दोलन गठित करें

एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने दिनांक 17 फरवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया है: -

भ्रष्ट बैंक अधिकारियों, प्रशासन और सत्ता के ऊंचे गलियारों में बैठे सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की साफ सांठगांठ से एक हीरे और आभूषण व्यापारी नीरव मोदी द्वारा राष्ट्रीयकृत यानी सरकारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 11,300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है, वह बीजेपी सरकार का बहुत करीबी बताया गया है। इसने एक बार फिर से यह बात उजागर कर दी है कि पूंजीवादी भारत में लोगों पर वित्तीय अपराध, भ्रष्टाचार और घातक आर्थिक हमले किस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। विश्वास में बैंकों में जमा किए गए कड़ी मेहनत से कमाये गए जनता के धन को छलने की ऐसी बदनीयत भरी कार्रवाई सत्तारूढ़ पूंजीवाद के राजनीतिक एजेंटों द्वारा कराई जा रही है, उन्हें साफ बच निकल जाने दिया जा रहा है और आखिरकार इन भ्रष्ट बैंकों के नुकसान की भरपाई करने के नाम पर लोगों के करोड़ों रुपये से इन भ्रष्ट बैंकों को भुगतान किया जा रहा है। जाहिर है कि अगर ये नापाक करतूतें बेरोकटोक होने दी गई, तो बेईमान व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा जो भी सत्ता में हैं, उनसे मिलिभगत करके जनता के धन की ऐसी दिन दिहाड़े डकैती, अधिक से अधिक बढ़ती जायेंगी और गरीब लोगों को इस तरह फिरौती के लिए बंधक बनाया जाता रहेगा जो पूरी तरह से जीवन की प्राथमिक सुरक्षा से भी वंचित हैं।

इसलिए, जरूरी है कि पीड़ित लोग एकजुट हो जाएं, जोरदार विरोध में उठ खड़ हों और एक जोरदार आंदोलन गठित करें जिसकी तीव्रता ही है जो अकेले ऐसे महा अपराधों और धोखाधड़ियों की पुनरावृति को रोकने के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकती है।

झूठे वायदों की आड़ में किसानों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के जबड़े में धकेल दिया

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गत 1 फरवरी को संसद में वर्ष 2018-19 का केंद्रीय बजट पेश किया है। हालांकि विभिन्न हलकों में इस बजट की तरह-तरह से आलोचनाएं हुई है, लगभग सभी एक बात कह रहे हैं कि यह बजट कृषि मुखी-किसानपरस्त बजट है। किसी-किसी समाचार पत्र ने यह बात भी लिखी है कि वोट के लिए 'जय किसान' का नारा लगाया गया है। लिखा है, 'कोई भी जोखिम न उठाकर... एकदम कंधे पर हल उठाये किसान के पास जा खड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी और उनके वित्त मंत्री अरुण जेटली'। कहने का लहजा ऐसा है कि मानों इस बजट के बाद ग्रामीण भारत के किसानों की हालत सुधर जाएगी। उनके चेहरे हंसी से खिल उठेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कथित 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए जोरदार कदम उठाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ जाएगी। लेकिन क्या बजट में सचमुच में ऐसी कोई व्यवस्था अपनायी गयी है जिससे किसानों के चेहरे मुस्कान से खिल उठें?

(शेष पृष्ठ 2 पर)

हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वायदे का क्या हुआ?

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर रोजगार के अवसर सृजन करने पर जोर दिया जाएगा। उनकी सरकार हर साल 2 करोड़ बेरोजगार को नौकरी देगी। चार साल बीत चुके हैं। मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने की बात तो दूर रही वास्तव में, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाई मोदी सरकार। इस साल के केंद्रीय बजट में रोजगार की कोई बात नहीं है बल्कि, 1 फरवरी को बजट पेश करने से पहले ही, वित्त मंत्रालय ने एक निर्देश में यह घोषणा की है कि पांच साल से खाली पड़े सरकारी पदों को खत्म कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार का रास्ता सुझाया है युवक बेकार न रहकर पकोड़े तलें।

आर्थिक विकास दर पर आंकड़ों का झगड़ा चल रहा है। 2018 में कितनी आर्थिक वृद्धि होगी - 6 प्रतिशत होगी या 7 प्रतिशत इसको लेकर गर्मागरम बहस छिड़ी हुई है। उससे रोजगार की बदहाल स्थिति क्या जरा भी बदल रही

(शेष पृष्ठ 4 पर)

विरोध प्रदर्शनकारियों ने कानून भंग कर दी 5 हजार गिरफ्तारियां

कोलकाता : 30 जनवरी को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त देशव्यापी जेल भरो कार्यक्रम के तहत स्थानीय सुबोध मल्लिक स्क्वायर से रानी रासमणि एवेन्यू में हजारों मजदूर-कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और पुलिस की घेराबंदी को तोड़कर कानून की अवज्ञा की। कार्यक्रम का नेतृत्व एआईयूटीयूसी के पश्चिम बंगाल के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड ए.एल. गुप्ता और राज्य सचिव कॉमरेड दिलीप भट्टाचार्य न किया।

एआईयूटीयूसी पूरे देश में काम कर रहे लोगों के जीवन में सबसे खराब संकट के खिलाफ एक जोरदार आंदोलन गठित करने की कोशिश कर रहा है। मुद्रास्फीति पर रोक, सभी को राशन, 18 हजार रुपए मासिक न्यूनतम मजदूरी, स्थायी काम में अस्थायी श्रमिकों की भर्ती पर रोक के साथ ही साथ आईसीडीएस-मिड-डे मील वर्करों को श्रमिकों का दर्जा, स्कीम श्रमिकों को सरकारी कर्मचारियों की मान्यता, 3000 रुपये न्यूनतम पेंशन देने और बैंक में एफआरडीआई बिल, कॉर्पोरेट पूंजी एफडीआई को वापस लेने आदि 12-सूत्री मांगों को लेकर मजदूर आन्दोलन गठित किया जा रहा है। श्रमिकों के आंदोलन में शामिल हुए बिना उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार लगातार श्रम कानूनों को मालिकों के हितों में बदलती जा रही हैं। सरकार की इन जनविरोधी और मजदूर-कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ एआईयूटीयूसी समेत 10 केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने 30

जनवरी को देश भर में सत्याग्रह/जेल भरो आन्दोलन करने का निर्णय लिया था।

यद्यपि भारत के सभी राज्यों में मजदूर-कर्मचारियों द्वारा कानून भंग किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में सीटू सहित कुछ अन्य संगठन इस समय कानून भंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए केवल एआईयूटीयूसी ने 'जेल भरो' के

(शेष पृष्ठ 5 पर)

झूठे वादों की आड़ में ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बजट में लिए गए उपायों का विश्लेषण करने से पहले, विचार करके देखा जाए कि क्या-क्या उपाय करने से किसानों की समस्या थोड़ी बहुत हल हो सकती है। किसानों को खेती करने के लिए पहले बीज की आवश्यकता होती है पिछले तीन-चार वर्षों में बीज के दाम 3-4 गुना बढ़े हैं। कुछ बीजों के दाम दस गुना तक हो गये हैं बीजों के दाम कम करने की आवश्यकता है, किसानों की क्रय शक्ति के अन्दर ले आने की जरूरत है। फिर खेती करने के लिए पानी चाहिए। देश की ज्यादतर जमीन अभी असिंचित है। सरकारी पहलकदमी से जितनी कुछ सिंचाई की व्यवस्था हुई थी वह भी लंबे समय तक उपेक्षा के कारण दिन-प्रतिदिन घट रही है। किसानों ने अब अपनी पहलकदमी से ट्यूबवेल लगाकर सिंचाई की व्यवस्था कर ली है। ये ट्यूबवेल या तो बिजली से चलते हैं या डीजल से। इसलिए पानी का इंतजाम करने के लिए सरकारी पहलकदमी से सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है। खेती-बाड़ी के लिए बिजली और डीजल, गरीब, मझोले और सीमांत किसानों को मुफ्त सप्लाई करने की जरूरत है। अब रासायनिक खाद के बिना कृषि कार्य असम्भव है। इन खादों के दाम भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इसलिए खाद के दाम घटाने की जरूरत है और किसान को कम दामों पर खाद समय पर मिलने की व्यवस्था करने की जरूरत है। कीटनाशकों की बात तो छोड़ ही दीजिए। इन पर तो सरकार का कोई नियंत्रण ही नहीं है। कंपनियां मनमाने दाम तय करती हैं और मनमनाना मुनाफा लूटती हैं। फिर इस मामले में, नकली कीटनाशकों की बाजार में भरमार है। इसलिए किसान चाहते हैं कि कीटनाशकों पर सरकारी नियंत्रण लागू हो, बाजार से नकली कीटनाशक दूर हों, कीटनाशक सस्ते हों। हर कोई समझता है कि खेती करने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है। खाद-बीज-तेल के दाम जितने बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किसान के घर में पूँजी है कहाँ! सरकारी बैंक निम्न-मध्यम-सीमान्त किसानों या बटाईदार किसानों को कर्ज देना नहीं चाहते। वे उद्योगपतियों, अमीर किसानों को ऋण देते हैं इसीलिए किसान पूँजी के लिए ग्रामीण महाजनों और सूदखोरों के पास जाने को मजबूर होते हैं। 6 या 10 रुपये सैकड़ा तक ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं। ये सब सूदखोर महाजन इससे फायदा उठाते हैं। किसान इस हालत से छूटकारा पाना चाहते हैं। किसान चाहते हैं बीज के दाम कम हों, खाद के दाम कम हों, कीटनाशकों के दाम कम हों, सरकार की ओर से सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जाये। खेती के लिए मुफ्त बिजली और डीजल दिया जाये। बिना ब्याज के या थोड़े-बहुत ब्याज पर उन्हें पैसा दिया जाए ताकि वे आसानी से कृषि कार्य कर सकें। इससे खेती का लागत खर्च कम हो जाएगा और उनके जीवन में कुछ राहत मिलेगी।

लेकिन क्या इस बारे में किसी योजना की घोषणा की गई है? क्या इस बजट में इन सब समस्याओं को हल करने की दिशा दी गयी है? इस बजट के बाद क्या खाद-बीज-तेल-बिजली-पानी-खेती के लिए पूंजी कम लागत पर उपलब्ध होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा इस संबंध में बजट में कोई घोषणा नहीं की गयी है और कोई योजना भी पेश नहीं की गयी है। तब इस बजट के बाद क्या होगा? बजट के बाद भी खाद के दाम, बीजों के दाम बढ़ते रहेंगे, ऋण और ब्याज का बोझ बढ़ता रहेगा जिसके चलते किसानों की आत्महत्या की घटनायें बढ़ती रहेंगी। इस सत्य को समझने के लिए, बजट विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है।

इस देश के आम किसानों का रोजमर्रा का तजुर्बा क्या है? वह यह है कि कितना कष्ट उठाकर, ऐड़ी-चोटी का पसीना बहाकर वे जो फसल उगाते हैं, उसका बाजार भाव लगभग ना के बराबर मिलता है। जूट, धान, कपास, गन्ना, गेहूँ, आलू आदि की खेती करने वालों के दिल दहला देने वाले तजुर्बों की बात सर्वविदित है। पिछले दिनों बाजार भाव नहीं मिलने से आलू-टमाटर उगाने वाले किसानों ने आलू-टमाटर को सड़कों पर बिखेर दिया। बाकी फसलें भी औने-पौने दामों पर बिकी। सरकारी खरीद न के बराबर होती है। जो कुछ भी बिकती है, वह भी ज्यादातर आढ़तियों की मार्फत ही बिकती है। सारे देश में स्थिति ऐसी ही है। पश्चिम बंगाल में जूट की सरकारी खरीद नहीं होती है। महाराष्ट्र में कपास उगाने वाले किसानों को उसके पूरे दाम नहीं मिलते। दूग्ध-उत्पादकों को दूध के वाजिब दाम नहीं मिलने से दूध को वे सड़कों पर बहा देते हैं। आंध्रप्रदेश के मुंगफली उगाने वाले किसान या उत्तर प्रदेश के प्याज उगाने वाले किसान वाजिब दाम न मिलने पर फसल गलाकर जैविक खाद तैयार करते हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश के 6 किसान बीजेपी सरकार द्वारा कराई गयी फायरिंग में मारे गये थे। स्वाभाविक कारण से ही फसलों के लाभकारी दाम की मांग को लेकर किसान आंदोलन उभर रहा है।

इस आंदोलन के दबाव में, बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री जेटली ने अपने बजट भाषण में कहा है, ''आगामी खरीफ से सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना करने का फैसला लिया गया। यदि एमएसपी से बाजार भाव गिरता है, तो उस भावान्तर की सब्सिडी दी जाएगी।'' आइए देखें कि देखने में इस लोकलुभावने वायदे के पीछे केंद्र सरकार की कितनी बड़ी विनाशकारी योजना है।

केंद्र सरकार यदि अपने वायदे के मुताबिक सीधे किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पाद को खरीदती है तो एमएसपी और बाजार भाव के अन्तर की सब्सिडी देने का सवाल ही क्यों उठेगा? किसान सरकार को फसल देंगे, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार किसानों को दाम देगी। यहां 'बाजार भावान्तर' या 'सब्सिडी' आदि का सवाल उठने की कोई बात ही नहीं है। बाजार भावान्तर का सवाल तो तभी उठ सकता है जब किसान अपनी फसल को लेकर जेटली साहब की घोषणा के अनुसार बाजार में जाएंगे और उसे किसी व्यापारी को बेच देंगे। फिर यह मामला ऐसा है: 1) सरकार किसानों की फसलों को नहीं खरीदेगी, 2) व्यापारी या विभिन्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किसानों की फसलों को खरीदेंगी। इस खरीद के मामले में यदि दाम एमएसपी से कम है, तो इस भावान्तर की राशि किसानों को सरकार अदा करेगी।

सवाल उठता है कि अगर सरकार किसानों से खाद्य पदार्थों की खरीद नहीं करती है, तो सभी खाद्यान्न बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और व्यापारियों के हाथों में चले जाएंगे। क्या खाद्य सामग्रियों पर उनका यह पूर्ण नियंत्रण देश में एक विकट स्थिति पैदा नहीं कर देगा? इसका परिणाम क्या होगा? वे मनमाने दामों पर किसानों से उनकी फसल को खरीद लेंगे,और वे जनता को मनमाने दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमायेंगे। किसानों की मदद के नाम पर इस तरह बीजेपी सरकार तमाम कृषि जिन्सों को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उसके एजेंटों को देने की योजना बना रही है।

सरकार किसानों की फसलों को सीधे नहीं खरीदती है, तो सरकारी विपणन की जो व्यवस्था (जेसीआई, सीसीआई आदि) अभी तक विकसित हुई है, वह लुप्त हो जाएगी और किसान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के रहमोकरम पर निर्भर हो जायेंगे। वे कम्पनियां मिलकर फसल बिक्री के मौसम में फसलों के बाजार भाव को गिरा देंगी (अब जैसे आढ़ती घटा देते हैं) और किसानों को औने-पौने दाम पर अपनी फसलों को बेचने के लिए मजबूर कर देंगी। अभी भी ऐसा ही होता है। इस नीति के फलस्वरूप यह प्रक्रिया और भी जोर पकड़ेगी। क्योंकि अब जिन सब कृषि जिन्सों को सरकार बाजार से सीधे खरीदती है उसका बाजार पर सामान्य होने पर भी एक असर पड़ता है। तब कोई प्रभाव ही नहीं रहेगा। व्यापारियों के लिए एकदम खुली छूट होगी। यानी मनमाने दाम कमाओ, मनमाने दामों पर खरीदो, मनमाने मुनाफे कमाकर अपनी तिजोरियां भरो।

असल में, केन्द्र की बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री ने देश के किसानों को जो तथाकथित अच्छी खबर दी है, वह पिछले साल से ही उन्होंने मध्य प्रदेश में शुरू की हुई है। परियोजना का नाम दिया गया है भावान्तर भुगतान योजना। मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि किसानों को इस परियोजना का लाभ नहीं मिला, इससे केवल उन्हीं बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा हुआ है, जो बड़ी-बड़ी कृषि मण्डियों पर नियंत्रण रखते हैं। इसी व्यवस्था को वे अब किसानों के कल्याण के नाम पर पूरे देश में लागू करना चाहते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की फसलों को खरीदने की सरकार की कोई इच्छा ही नहीं है। पिछले कई वर्षों में भी, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल बहुत मामूली खरीदी है। अनुमान के मुताबिक, पिछले साल, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में कम दामों पर फसलों को बेचने के लिए मजबूर किया गया, जिससे पूरे देश में किसानों को 32 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस साल के बजट को तथाकथित 'सब्सिडी' देने के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? क्या मामूली-सी राशि से पूरे देश में एमएसपी की तुलना में कम दामों पर फसल बेचने वाले किसानों को सब्सिडी दी जा सकेगी?

फसल का लागत खर्च कैसे तय होगा? सरकार थोक बाजार भाव के अनुसार फसल का लागत खर्च तय करेगी। लेकिन किसान तो बाजार से थोक बाजार भाव से कृषि में काम आने वाली चीजों को नहीं खरीदते। वे खुदरा भाव से चीजें खरीदते हैं जो थोक भाव की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। नतीजतन, थोक मूल्य के आधार पर हिसाब लगाने से निर्धारित किया जाने वाला डेढ़ गुना एमएसपी वास्तव में किसानों के उत्पादन खर्च के बराबर या उससे कम होगा। नतीजतन, लागत खर्च पर 50% लाभ देने की जो बात स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में कही गयी थी उससे मुकरना हो जाएगा। जहां उत्पादन लागत के डेढ़ गुना दाम देने की घोषणा भी की गयी है, लेकिन वहीं आँकड़ों की बाजीगरी से इस तरह धोखा भी दिया गया है। यह है केंद्र कीं वर्तमान बीजेपी सरकार की भूमिका।

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने कहा है कि रबी की अधिकांश घोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से कम से कम डेढ़ गुना तय किया जा चुका है। लेकिन इस एमएसपी के अनुसार क्या कहीं किसानों की फसल खरीदी गई? वित्त मंत्री चाहे जितना भी दावा करें, मगर सच्चाई यह है कि वित्त मंत्री के कहने के मुताबिक देश में कहीं भी उत्पादन लागत खर्च से कम-से-कम डेढ़ गुना दामों पर किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। एक भी किसान को इससे कोई फायद नहीं हुआ। नतीजतन, यह आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस साल के घोषित एमएसपी का क्या हाल होगा।

हम बहुत पहले से ही कहते आये हैं कि किसानों और आम लोगों के कल्याण के लिए सरकार एक ऐसी उचित व्यवस्था कर सकती है जिससे कि खाद्यान्न और रोजमर्रे की जरूरत की चीजों का थोक और खुदरा तमाम राष्ट्रीय व्यापार-वाणिज्य सरकार अपने हाथ में ले ले। सरकार कृषि उत्पादों को सीधे किसानों से लाभकारी दामों पर खरीदे और उन्हें सब्सिडी देकर

(शेष पृष्ठ 4 पर)

मिड-डे मील कर्मियों ने किया बजट कटौती का विरोध, पुतला फूंका

भिवानी में सरकार का पुतला फूंकती हुई मिड-डे मील कार्यकर्ता

भिवानी (हरियाणा) : 6 फरवरी को मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन सम्बन्धित एआईयूटीयूसी के बैनर तले मिड-डे मील कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय बजट में मिड-डे मील के मद में आवंटन और मिड-डे मील कर्मियों का मेहनताना नहीं बढ़ाये जाने पर रोष व्यक्त करते हुए हांसी गेट पर सरकार का पुतला फूंका। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में मिड-डे मील कर्मी दिनोद गेट स्थित चेतराम प्रजापति धर्मशाला में इकट्ठा हुई और शहर में रोष प्रदर्शन किया। इस रोष प्रदर्शन की अगुवाई मिड-डे-मील कार्यकर्ता यूनियन की जिला कमेटी और एआईयूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड राजकुमार बासिया ने की।

उन्होंने मिड-डे-मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, न्यूनतम वेतन 18000 रुपये मासिक देने, कम से कम 3000 रुपये पेन्शन देने, इस सेवा को शिक्षा विभाग में विलय करने, मिड-डे मील स्कीम की देखरेख के लिए अलग से स्टाफ भर्ती करने, छूट्टियों के दौरान का उनका मानदेय भत्ता न काटा जाने और समय पर भुगतान किया जाने, हाजिरी रजिस्टर, मासिक बंधा वेतन, महंगाई के हिसाब से सालाना बढ़ोतरी करने, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने, जीवन बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सवेतन अवकाश आदि देने, सर्दी-गर्मी के हिसाब से साल में दो वर्दियां देने, बीमार पड़ने पर निःशुल्क इलाज कराने, रसोई में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, बच्चों का कुपोषण दूर करने हेतु गुणवत्ता वाला भोजन देने के वास्ते मिड-डे मील योजना का बजट बढ़ाने और मिड-डे-मील स्कीम के क्रियान्वयन को पंचायतों को न सौंपे जाने की मांग की।

मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए यूनियन की जिला प्रधान मीरा देवराला ने कहा कि मिड-डे मील सरकारी स्कीम है। इसके तहत मिड-डे मील कार्यकर्ता अपनी सेवाएं सरकारी स्कूलों में प्रदान कर रही हैं। मिड-डे मील कार्यकर्ता जब सरकारी काम करती हैं, तो सरकार को अपना श्रमिक-कर्मचारी भी मानना चाहिए। लेकिन वह मिड-डे मील कर्मियों को श्रमिक ही नहीं मान रही है, न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है और कोई सामाजिक सुरक्षा भी नहीं दे रही है। इतनी महंगाई में भी उनको मामूली सा मेहनताना महज 2500 रुपये मासिक और वह भी साल में सिर्फ 10 महीने का। यह मामूली सा मेहनताना भी समय पर नही मिल पा रहा है और महंगाई बढ़ने पर भी कई साल से नहीं बढ़ा है। इससे परिवार का गुजारा नहीं होता है। मिड-डे मील कर्मियों को सरकार श्रमिक की बजाय ''कार्यकर्ता'' और वेतन की बजाय ''मानदेय'' की संज्ञा देकर दरअसल मिड-डे मील कर्मियों को ठग रही है। जबकि 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन ने सभी स्कीम वर्करों को अनिवार्य रूप से श्रमिक का दर्जा देने, मासिक न्यूनतम वेतन देने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार इन सिफारिशों को लागू नहीं कर रही है। स्कीम वर्करों ने नवम्बर 2017 में ससद पर महापड़ाव और 17 जनवरी 2018 को देशव्यापी हड़ताल करके अपनी ये मांगें बुलंद की हैं और वे कई बार ज्ञापन देकर मांग कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इससे मिड-डे मील कर्मियों में भारी रोष है।

मिड-डे मील की जायज मांगों का समर्थन करते हुए एआईयूटीयूसी के जिला कमेटी सदस्य राजकुमार बासिया ने कहा कि इस मामले में केन्द्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और मौजूदा बीजेपी सरकार की नीतियों में कोई फर्क नहीं है। यहां तक कि किसी प्रदेश सरकार ने भी ऐसी पहल नहीं की कि मिड-डे मील कर्मियों के योगदान का सम्मान करते हुए उन्हें मेहनताना ही ढंग का दे दे। जबकि भारतीय श्रम सम्मेलन व अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कन्वेन्शनों का पालन करना और कमेटियों की सिफारिशों को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मिड-डे मील स्कीम सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है और स्कूलों से संबंधित है इसलिए इसका क्रियान्वयन किसी और के हवाले करना गलत है। सरकार का यह कदम इस स्कीम को भ्रष्टाचार की दलदल में धकेल देगा। इसके लिए बजट में कटौती कर रही है। उन्होंने आशंका व्यक्त की कि सरकार मिड-डे-मील स्कीम जैसी महत्वपूर्ण स्कीम से अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। उन्होंने मिड-डे मील कर्मियों से ज्वलंत मांगों को लेकर आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया।

इसमें कौशल्या दुल्हेड़ी, पूजा सांगा, मनोरमा व कमलेश लोहरवाड़ा, उषा मुण्ढाल, अनीता व सुषमा बामला, सुमित्रा झिंझर और बिमला पैतावास भी शामिल थी।

गुना जिला का दूसरा युवा सम्मेलन सम्पन्न

गुना (मध्य प्रदेश) : आल इण्डिया डीवाईओ, गुना जिले का दूसरा युवा सम्मेलन 4 फरवरी को सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन की शुरुआत शास्त्री पार्क से रैली के रूप मे हुई जो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए 'शराब नही,,, शिक्षा और रोजगार चाहिए', 'हर हाथ को स्थायी रोजगार दो' के नारों के साथ हाट रोड नगर पालिका पर जाकर खुले अधिवेशन में तब्दील हो गई।

रैली को एआईडीवाईओ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉ. विश्वजीत हरोडे व मजदूर नेता नरेन्द्र भदौरिया ने संबोधित किया।

खुले अधिवेशन में शहर के कई जाने-माने जनवादपसंद लोग शामिल हुए।

शाम को होटल प्रेमश्री परिसर में आयोजित प्रतिनिधि अधिवेशन की शुरुआत में कॉ. विश्वजीत हरोडे ने संगठन का ध्वजारोहण किया।

सम्मेलन के अंत मे जिला कमेटी चुनी गई जिसमें चंचल साहु को जिलाध्यक्ष व नीरज बैरागी को जिला सचिव चुना गया। 35 सदस्यों की एक कॉउंसिल भी गठित की गई।

सम्मेलन का समापन 'हम होंगे कामयाब' गीत के साथ हुआ।

गुना में जिला स्तरीय युवा सम्मेलन में शामिल लोग। ऊपर मंच पर बैठे नेतागण

एआईडीवाईओ का जौनपुर जिला सम्मेलन सम्पन्न

जौनपुर (उ.प्र.) : 28 जनवरी को युवा संगठन एआईडीवाईओ का जौनपुर जिला सम्मेलन सल्तनत बहादुर इ.का. बदलापुर के नरसिंह बहादुर सभागार में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।

सम्मेलन के पूर्व एसयूसीआई(सी)के सब्जी मण्डी स्थित कार्यालय से एक जुलूस निकाला गया जो मुख्य मार्ग एवं इंदिरा चौक से होते हुए इण्टर कालेज के सभागार में पहुंच कर सभा में तब्दील हो गया। प्रारम्भ में झण्डोत्तोलन एवं शहीद वेदी पर माल्यार्पण किया गया।

सम्मेलन की अध्यक्षता एआईडीवाईओ के जिलाध्यक्ष कॉ. महेन्द्र कुमार मौर्य ने की एवं संचालन जिला सचिव कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल ने किया। एसयूसीआई(सी) के उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी सदस्य कॉ. जगदीश चन्द्र अस्थाना कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे।

सम्मेलन में संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कॉ. रविशंकर मौर्य, प्रदेश सचिव कॉ. मकरध्वज चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष कॉ. जयप्रकाश मौर्य, सचिव मण्डल के सदस्य कॉ. रामकुमार यादव एवं प्रदेश कोषाध्यक्ष कॉ. कमलेश मौर्य आदि ने अपनी बात रखी। वक्ताओं ने फासीवाद के बढ़ते खतरे, लगातार बढ़ती बेरोजगारी, नशाखोरी, अश्लीलता, कुसंस्कृति के मौजूदा हालत में एआईडीवाईओ की भूमिका पर प्रकाश डाला।

सम्मेलन में 13 सदस्यीय जिला कमेटी गठित की गई। इसमें सर्वसम्मति से कॉ. इन्दु कुमार शुक्ल को जिलाध्यक्ष, कॉ. दिनेशकान्त मौर्य को जिला सचिव, कॉ. विजय प्रकाश गुप्त को कोषाध्यक्ष एवं राजबहादुर विश्वकर्मा, विनोद कुमार मौर्य, राधेश्याम विश्वकर्मा, शिवप्रसाद विश्वकर्मा, रवीन्द्र पटेल, राकेश कुमार निषाद, देवीशंकर निषाद, प्रदीप मौर्य एवं दिवाकर गोसाईं को सदस्य चुना गया।

हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वायदे का क्या ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

है? पिछले आठ वर्षों में, इस वर्ष सबसे कम रोजगार दर रही। 2013-14 से लेकर 2015-16 तक इन तीन वित्तीय वर्ष में, देश में रोजगार नहीं बढ़े उल्टे 53 लाख रोजगार कम हो गये। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2018 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष के अंत तक भारत में बेरोजगारों की संख्या में और भी वृद्धि होगी।

निर्माण उद्योग, सूचना तकनीक (आई.टी.) जैसे क्षेत्रों में, कुछ नौकरियां अब तक होती थी, अब उनमें भी कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। प्रधान मंत्री की नोटबन्दी ने कई लोगों के रोजगार छीन लिये हैं, जीएसटी की मार पड़ने से कई छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार खुद कह रहे थे कि नोटबन्दी-जीएसटी जैसे अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी चमक-दमक प्रिय प्रधान मंत्री ने यह सब किया। साल दर साल बजट पेश किये गये हैं, योजनाओं के पहाड़ समान स्मारक तैयार किये गये हैं, लेकिन रोजगार कटौती की दर धीरे-धीरे बढ़ रही है। नौकरी के लिए देशभर में बेरोजगार युवक-युवतियां का हाहाकार अब आर्तनाद में बदल गया है। स्वच्छ भारत, गौरक्षा, नोटबन्दी, मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टार्ट-अप इण्डिया, सबका साथ सबका विकास–इस तरह के लुभावने नारे देकर भी बेरोजगारी के असहनीय नजारे को ढक नहीं पा रहे हैं।

कुछ साल पहले, उत्तर प्रदेश में चपरासी के 366 पदों के लिए 23 लाख युवक-युवतियों ने आवेदन किया था। इनमें से 255 पीएचडी, 20 लाख से अधिक इंजीनियर, कई लाख स्नातकोत्तर थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों में ग्रुप-डी के 6,000 रिक्त पदों के लिए 24 लाख बेरोजगारों ने आवेदन किये थे। 300 से अधिक आवेदकों ने मालदा मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर में शव वाहक पद के लिए आवेदन किया था। इनमें से कई एम फिल, पीएचडी की डिग्रीधारी थे कोई तो दो बार पोस्ट ग्रेज्यूवेशन किये हुए था। 300 में से हर तीसरा व्यक्ति स्नातक था। दक्षिण दिनाजपुर के बेलुरघाट थाने अन्तर्गत सिविक वालन्टियर के 244 पदों के लिए 12 घंटे के अन्दर लगभग 7,000 आवेदन प्राप्त हुए। देश के दूसरे राज्यों का भी यही हाल है।

आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के बहुप्रचारित आईटी मॉडल का बहुत अरसा पहले पर्दाफाश हो चुका है। एक समय, सीपीएम सरकार ने हल्दिया में नये रोजगार देने के सब्जबाग दिखाये थे। वर्तमान मुख्यमंत्री की नये रोजगार देने के झूठे दावों की हकीकत सभी जानते हैं। नरेन्द्र मोदी-अमित शाह के बहु-प्रचारित गुजरात मॉडल की भी पोल खुल चुकी है। असंगठित क्षेत्र के अलावा, कहीं कोई काम नहीं है। ऐड़ी-चोटी का पसीना बहाकर भी, परिवार का गुजर बसर करना दूभर हो गया है। बेरोजगारी के इस संकट को देखकर, मोदी के एक करीबी अर्थशास्त्री, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तक ने कहा है, 'अण्डर इम्पलाइमेन्ट इज ए सीरियस प्रोब्लम' अर्थात् पूरे समय पर काम नहीं है, वाजिब तनख्वाह पर आधारित काम नहीं है। जितना कुछ है वह भी ठेके पर आधारित काम है। उदारीकरण के समर्थक अर्थशास्त्री लम्बे अरसे से रोजगार विहीन विकास की बात कर रहे हैं। अर्थात् देश का तो विकास हो रहा है लेकिन उससे रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। तब यह विकास देश के आम लोगों के किस काम का?

देश की यह भयावह तस्वीर प्रधानमंत्री के लिए अज्ञात नहीं है। इस तस्वीर पर पर्दा डालने के लिए ही, प्रधानमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को आसान रास्ता बतला दिया है। जो लोग रोजगार की समस्या को लेकर सरकार पर उंगलियां उठा रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है, 'किसी कार्यालय के सामने जो पकौड़े की दुकान खोले हुए है, वह क्या रोजगार नहीं कर रहा है? मानो रोजगार का मामला बच्चों का खेल हो! यह पकौड़े तलने के लिए ही क्या बेरोजगार युवक-युवतियों ने मोदी को समर्थन दिया था?

प्रधानमंत्री ने चालाकी से कहा है कि 70 लाख ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) के खाते को खोलना रोजगार देने का ही उदाहरण है। सच क्या है? वास्तव में, पीएफ मालिकों के खजाने में देय रुपये का 8.33 प्रतिशत की राशि का भुगतान स्वयं सरकार ने वहन किया है। कपड़ा, चमड़ा और जूता उद्योग के पैकेज में भी सरकार ने नए कर्मचारियों के पीएफ में अतिरिक्त 3.67 प्रतिशत के भुगतान की जिम्मेदारी ली है। वास्तव में, मालिकों द्वारा देय राशि को चुकाने की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा अपने कन्धों पर लिये जाने से ही खातों की संख्या बढ़ी है। वास्तव में, इसके साथ नए रोजगार सृजन का कोई लेना-देना नहीं है, एआईयूटीयूसी के महासचिव और ईपीएफ निगरानी परिषद के सदस्य कॉमरेड शंकर साहा ने यह बात कही है। सरकार ने पूँजीपतियों के लिए दानशाला खोल दी है और उसने बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार देने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है!

पकौड़ा तलने का नुस्खा देकर प्रधानमंत्री ने स्वयं ही कह दिया है कि रोजगार देने का कोई भी नया अवसर नहीं है। बजट में भी उसी का प्रतिफलन हुआ है जबकि प्रधानमंत्री और उनके दरबारी रोजगार की बाढ़ लाने का राग अलाप रहे हैं। क्योंकि, कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं। इसलिए, बेरोजगारों के रोष को शान्त करने के लिए ये सब राग अलापने की जरूरत है। बेरोजगारी की यह समस्या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन काल में भी थी, अब यह और भी बढ़ गयी है।

सरकार के नेता और मंत्री रूटिन की माफिक कहते जा रहे हैं कि बेरोजागारी की समस्या से निजात पाने के लिए कुछ समय इन्तजार कीजिए। मीडिया का प्रचार यह है कि 'मुक्त बाजार व्यवस्था' निजी पूंजी के मुनाफे के तकाजे से लगातार निवेश करेगी। तब तो रोजगार के अवसर धड़ा-धड़ बढ़ जायेंगे। लोगों की आय में वृद्धि होगी। सचमुच में ही क्या ऐसा है? निजी पूंजी निवेश के द्वार खोल देने से क्या नौकरियों के बाजार में आयी मन्दी दूर हो जाएगी? यह पूंजी निवेश उत्पादन उद्योगों में कितना हो रहा है? अधिकांश निवेश शेयर बाजार या सट्टेबाजी में हो रहा है।

विश्वव्यापी पूंजीपति बाजार के भयानक संकट में भारत भी फंसा हुआ है। देश में करोडों लोग हैं, लेकिन उनके पास खरीद शक्ति नहीं है। इसलिए कोई मांग नहीं है, नए उद्योग नहीं लग रहे हैं। लगे लगाये कारखानों में रोजगार की भारी कटौती हो रही है। बेरोजगारी की समस्या के रोग निवारण के लिए सेवा और सूचना तकनीक (आईटी) क्षेत्र में रोजगार का टोटका देकर ईलाज करने की कोशिश की गयी थी वह नाकाम हो गयी है। 2017 में इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट जैसी पहली कतार के आई.टी. क्षेत्र में 56 हजार इंजीनियरों की छंटनी हो चुकी है। उनमें से हर कोई उन्नत और आधुनिक तकनीकी विद्या को हासिल किये हुए है और मोटी रकम खर्च करके, पढ़ लिख कर नौकरी से पैसा कमाने का मौका पाये हुए था। यहां वहां हर जगह तालाबंदी हो रही रही है। बड़ी पूंजी के मालिक छोटी और मध्यम दर्जे की पूंजी को निगलते जा रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर और भी कम हो रहे हैं।

रोजगार पाने के लिए बेरोकटोक औद्योगीकरण की जरूरत है। औद्योगीकरण का अर्थ है बेरोकटोक नए-नए कल-कारखाने लगते जाना। लेकिन वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में यह क्या कदापि सम्भव है? लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़े तो यह कदापि सम्भव नहीं है। सरकार यदि सकारात्म रुख-रवैया लेकर चले तो इसके तहत भी 2-4 क्षेत्रों में सरकारी पहल पर श्रम प्रधान उद्योग लग सकते हैं। रेल-स्वास्थ्य-शिक्षा-बीमा-बैंक इत्यादि सेवा क्षेत्रों में सरकारी पहलकदमी बढ़ाकर कुछ रोजगार पैदा किये जा सकते हैं लेकिन सभी सरकारे असल में देश के असली मालिक धन कुबेरों की ताबेदार मात्र हैं। इसलिए यह काम उनके वश का नहीं है। बजट में 250 करोड़ रुपये से अधिक राशि कारपोरेट घरानों को टैक्स छूट में देने की घोषणा यही साबित करती है।

नतीजतन, करोड़ों पकौड़ा तलने वाले या कभी सरकारी पार्टी के हफ्ता वसूलने वाले के तौर पर रोजगार का रास्ता बता देना ही उनका संबल है। असहाय हालत में जी रहे बेरोजगारों के प्रति यह एक क्रूर मजाक है। इसका प्रति उत्तर एक दिन इस देश के नौजवान जरूर देंगे।

झूठे वादों की आड़ में ... |||

(पृष्ठ 2 का शेष)

आम जनता में बेच दे। अर्थात्, कृषि जिन्स, खासकर खाद्यान्न लाभकारी दामों पर खरीदने की जिम्मेदारी सरकार खुद ले। इस क्षेत्र में व्यापारियों को न घुसने दे। क्या केंद्र सरकार इस सही रास्ते को अपना रही है? नहीं, इसके विपरीत, केंद्र सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के रास्ते पर ही चल रही है। उसने अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अपना पल्ला झाड़ लिया है और असहाय गरीब किसानों को बहुराष्ट्रीय मगरमच्छों के जबड़ों में धकेल दिया है।

एक बात और यहां कहने की जरूरत है। ग्रामीण भारतीय परिवारों के आधे से ज्यादा लोग अब खेतमजदूर-ग्रामीण मजदूर हैं। केन्द्र की बीजेपी सरकार ने उनके लिए इस बजट प्रस्ताव में क्या व्यवस्था की है? मनरेगा में सौ दिन काम देने की बात कही गयी है लेकिन गौरतलब बात यह है कि पिछले साल बजट आवंटन का रुपया पूरी तरह खर्च ही नहीं कर पाये। उनके आचरण से यह साफ जाहिर है कि वे इसका महत्व धीरे-धीरे कम कर देना चाहते हैं। क्या इसमें कोई संदेह है कि ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में उनका ये नकारात्मक मनोभाव ग्रामीण भारत के असहाय गरीब लोगों को और भी समस्या में डाल देगा।

किसानों को भले ही नुकसान हो जाए, लेकिन इस बजट प्रस्ताव से सांसदों को फायदा होगा। देश की संसद में 429 सांसद करोड़पति हैं। लेकिन इन करोड़पति सांसदों का वेतन-भत्ता दुगुना कर दिया गया है। उनकी अन्य सुख-सुविधायें भी बढ़ायी गयी हैं। इसलिए बजट किसके फायदे के लिए है यह समझना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल है?

हमारी मांग है कि सरकार सीमान्त, गरीब और मध्यम किसानों की तमाम फसलों को लाभकारी दामों पर खरीद ले और सब्सिडी देकर उनकी सप्लाई व्यापक गरीब जनता तक पहुंचा दे। इस मांग को हासिल करने के लिए लाखों लाख किसानों के संगठित आंदोलन को गठित करना निहायत जरूरी है। ऑल इण्डिया किसान खेतमजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) इसी काम में लगा हुआ है।

बेरोजगारी के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने मनाया प्रदेशव्यापी विरोध दिवस

ग्वालियर : विरोध प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए कॉ. सुनील गोपाल

ग्वालियर (म.प्र.) : बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ आन्दोलन संगठित करते हुए एस.यू.सी.आई. (कम्युनिस्ट) ने 16 फरवरी को राज्य स्तरीय विरोध दिवस मनाया। इस दिन पार्टी की ग्वालियर जिला इकाई ने फूलबाग चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया।

इस अवसर पर अपने संबोधन में पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड सुनील गोपाल ने कहा कि आज पूरे देश में रोजगार के हालात बहुत चिन्ताजनक है। युवा वर्ग बेरोजगारी की मार झेल रहा है, यहां तक कि हताशा-निराशा के कारण कई युवक-युवतियां आत्महत्या तक कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा 4 लाख 70 हजार सरकारी पदों को खत्म किया जा रहा है। चुनाव जीतने के लिये मोदीजी ने 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा किया था। रोजगार देने की बात तो दूर रही, उल्टे हर साल 2 लाख रोजगार खत्म किये जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में 366 चपरासी के पदों के लिये 23 लाख से ज्यादा आवेदन आये। मध्यप्रदेश में पटवारी के 9 हजार पदों के लिये 12 लाख से ज्यादा आवेदन आये। ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय में चपरासी के 57 पदों के लिये 60 हजार से ज्यादा आवेदन आये। हैरानी की बात यह है कि चतुर्थ श्रेणी पदों के लिये भी एमबीए, बी.ई., पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट योग्यता वाले युवक-युवतियां तक आवेदन कर रहे हैं। आज युवा किसी भी तरह का रोजगार करने के लिये मजबूर हैं।

पार्टी की जिला कमेटी सदस्या कॉमरेड प्रतिज्ञा माझी ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब युवक सरकारों से रोजगार मांग रहे हैं तो देश के प्रधान मंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिये उनको पकोड़े बेचने की सलाह दे रहे हैं। आज शिक्षित युवक-युवतियां नौकरी हासिल करने के लिये प्रत्येक आवेदन पर 500 से 1000 रुपये तक खर्च करते हैं, जबकि आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें कोई खर्च नहीं होता। उन्होंने मांग की कि सरकार को आवेदन प्रक्रिया नि:शुल्क करनी चाहिये एवं आवेदकों की परीक्षा यात्रा को भी नि:शुल्क करना चाहिये। युवकों को गुजारे लायक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का संचालन पार्टी के जिला कमेटी सदस्य रूपेश जैन ने किया। इस अवसर पर रचना अग्रवाल, आभा भूभरकर, श्रुति शिवहरे, धीरेन्द्र शिवहरे, लालू पाल, प्रकाश माहौर, महेश माहौर, अभिषेक पवार, प्रदीप माहौर, आदि उपस्थित थे। **गुना :** बेरोजगारी के खिलाफ 16 फरवरी को गुना के हनुमान चौराह पर एसयूसीआई(कम्युनिस्ट) द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया।

विरोध प्रदर्शनकारी...

(पृष्ठ 1 का शेष)

संयुक्त निर्णय को लागू किया।

जुलूस की शुरुआत में, एआईयूटीयूसी नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने सरकारी नौकरियों में लाखों रिक्त पदों को खत्म किये जाने का विरोध किया।

सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी में उसी मांग पर, उसी दिन कानून का उल्लंघन किया गया था। जब मजदूरों और मेहनतकश लोगों ने कंचनजंगा स्टेडियम से सुव्यवस्थित जुलूस की शक्ल में एसडी कार्यालय की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो एक बड़े पुलिस बल ने जुलूस को रोक दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प में एआईयूटीयूसी दार्जिलिंग जिला सचिव कॉमरेड क्षितिज रॉय सहित पांच प्रदर्शनकारी घायल हो गए। पुलिस ने छह सौ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। कॉमरेड अभिजीत राय, शंकर गांगुली, समंदर अली, नासिर मोहम्मद, खितीश रॉय, जॉय लॉ और अन्य ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया।

झारखण्ड राज्य का छठा छात्र सम्मेलन सम्पन्न

ऑल इण्डिया डीएसओ का झारखंड राज्य का छठा सम्मेलन रांची में 4 फरवरी को आयोजित किया गया। झारखंड के विभिन्न जिलों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य वक्ता थे एसयूसीआई (सी) के राज्य सचिव कॉमरेड रॉबिन समाजपति। अन्य वक्ताओं में ऑल इण्डिया डीएसओ के अखिल भारतीय अध्यक्ष और महासचिव क्रमश: कॉमरेड कमल साई और कॉमरेड अशोक मिश्रा ने भी इस अवसर पर बात रखी। राजनीतिक परिस्थिति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद संगठनात्मक रिपोर्ट रखी गई। बड़ी संख्या में छात्र प्रतिनिधियों ने चर्चा में भाग लिया।

72 सदस्यीय राज्य कमेटी का प्रस्ताव सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। कॉमरेड अशरनी पाल को राज्य अध्यक्ष और कॉमरेड समर महतो को राज्य

रांची : छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कॉ. अशोक मिश्रा

सचिव चुना गया। कॉ. सोहन महतो को कोषाध्यक्ष और कॉ. जीवन यादव को कार्यालय सचिव के रूप में चुना गया। 120 सदस्यों वाली एक राज्य परिषद भी निर्वाचित हुई।

अखबारी कतरन

चार साल में राजनीतिक दलों को नौ चुनावी ट्रस्टों से मिले 637.54 करोड़

नई दिल्ली : वर्ष 2013-14 से 2016-17 के बीच नौ चुनावी ट्रस्टों ने राजनीतिक दलों को 637.54 करोड़ रुपये का चन्दा दिया। इनमें सबसे ज्यादा चन्दा भाजपा को मिला। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा को इस अवधि में 488.94 करोड़ और कांग्रेस को 86.65 करोड़ रुपये चन्दे में मिले हैं। चुनावी ट्रस्टों की ओर दिए गये कुल चन्दे में से 92 फीसदी यानी करीब 588.44 करोड़ रुपये पांच राष्ट्रीय दलों को मिले हैं। वहीं 16 क्षेत्रीय दलों को चन्दे में महज 7.70 फीसदी यानी 49.09 करोड़ रुपये मिले हैं। भाजपा और कांग्रेस ही दो राजनीतिक दल हैं जिन्हें हर वित्तीय वर्ष में चुनावी ट्रस्टों से चन्दा मिलता है। राजनीतिक दलों को 2013-14 के दौरान 85.37 करोड़, 2014-15 में 177.40 करोड़, 2015-16 में 49.50 करोड़ और 2016-17 में 325.27 करोड़ रुपये का चन्दा मिला। 2013-14 और 2016-17 में नौ रजिस्टर्ड चुनावी ट्रस्टों ने कुल 637.54 करोड़ रुपये का दान दिया। इनमें से दो ट्रस्टों प्रूडेंट और समाज इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दो बार से ज्यादा बार चन्दा दिया। (एजेंसी)

दिलीप सरोज के हत्यारों को गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की उठी मांग

इलाहाबाद (उ.प्र.) : 12 फरवरी को छात्र संघ भवन पर एआईडीएसओ के बैनर तले छात्रों ने राज्य सरकार का पुतला दहन किया। छात्रों ने दिलीप सरोज की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

विदित रहे कि रेस्तरां में अनजाने में छू जाने पर असहिष्णु हो गए बेखौफ दबंगों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एलएलबी के छात्र दिलीप सरोज की लोहे की रॉड व ईंट से क्रूरतापूर्वक पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। इस घटना ने समाज में बढ़ती असहिष्णुता को एक बार फिर उजागर कर दिया है। इस घटना ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है।

एआईडीएसओ ने दिलीप सरोज के हत्यारों को गिरफ्तार करने और कड़ी सजा देने की मांग की।

प्रदर्शन में संदीप, भानुप्रताप, पवन, हरिकेश, विजय, प्रताप, सत्यकेश, चन्द्रबलि, सुनील, रंजन शाह आलम, विवेक, अभय, अनुराग, कुलदी आदि कई छात्र शामिल थे।

खतरनाक असमानता

यह चिन्ता का विषय है कि भारत में आर्थिक असमानता बढ़ती ही जा रही है। गरीबी उन्मूलन पर काम करने वाली संस्था 'ऑक्सफैम' की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल में जितनी सम्पत्ति पैदा हुई, उसका 73 प्रतिशत हिस्सा देश के 1 फीसदी धनाढ्य लोगों के हाथों में चला गया, जबकि नीचे के 67 करोड़ भारतीयों को इस सम्पत्ति के सिर्फ एक फीसदी, यानी सौवें हिस्से से संतोष करना पड़ा है। 2016 के इसी सर्वे के अनुसार भारत के 1 फीसदी सबसे अमीर लोगों के पास देश की 58 फीसदी सम्पत्ति थी। हमारे यहां इतनी तेजी से बढ़ती असमानता दुनिया के नामी अर्थशास्त्रियों को भी चकित किये हुए है। दावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना सम्मेलन शुरू होने के कुछ ही घंटों पहले जारी इस रिपोर्ट के अनुसार बाकी दुनिया का हाल भी अच्छा नहीं है। पिछले साल दुनिया की सम्पत्ति में हुए कुल इजाफे का 82 प्रतिशत हिस्सा महज एक प्रतिशत अमीर आबादी के हाथ लगा, जबकि 3.7 अरब लोगों की सम्पत्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऑक्सफैम के सालाना सर्वे को लेकर दुनिया भर में उत्सुकता रहती है और इस पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सम्मेलन में चर्चा भी होती है। आय असमानता की बढ़ती खाई और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दे भी सम्मेलन के एजेण्डे में शामिल रहते हैं। अगर यह सम्मेलन आर्थिक असमानता कम करने का कोई सूत्र ढूंढ़ सके, तो इसे जरूर सार्थक समझा जाएगा, वरना सुपर अमीरों की पिकनिक तो इसे कहा ही जाता है। आर्थिक असमानता के चलते आज हर जगह आम जनता में भारी आक्रोश है, जिसकी अभिव्यक्ति अराजकता और हिंसक प्रदर्शनों में हो रही है। अमीरों के पास सम्पत्ति इकट्ठा होने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस सम्पत्ति का बड़ा हिस्सा अनुत्पादक होकर अर्थतंत्र से बाहर हो जाता है। उनका उपभोग न तो उत्पादन में कोई योगदान करता है, न ही उससे विकास दर को गति मिल पाती है। करोड़ों की गाड़ियां, लाखों की घड़ियां और पेन, बिटकॉइन जैसी आभासी मुद्रा में लगा हुआ पैसा क्या किसी पिछड़े देश में कोई रोजगार पैदा करता है? ऑक्सफैम की रपट को एक अर्थ में उदारीकरण और भूमण्डलीकरण पर की गयी टिप्पणी भी माना जा सकता है। दुनिया में पूंजी के अबाध प्रवाह के बावजूद फायदा उन्हीं के हिस्से गया, जो पहले से समृद्ध थे। नयी व्यवस्था में सरकारों का रोल घट जाने से राजनीति भी गरीबों के पक्ष में नीतियां बनाने के बजाय उन्हें भरमाने पर केन्द्रित हो गयी है। मनरेगा जैसी कुछ गरीब समर्थ नीतियां बनी भी तो उनका जोर कमजोर वर्ग को उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की बजाय उन्हें किसी तरह जीवित रखने पर रहा है। बहरहाल, असमानता के मुद्दे को टालते जाने की भी सीमा है। कहीं ऐसा न हो कि दुनिया ऐसी अराजकता की शिकार हो जाए, जिससे उबरने की कल्पना भी मुश्किल लगने लगे।

(साभार नवभारत टाइम्स, 23 जनवरी 2018)

मेट्रो किराया वृद्धि का विरोध

नई दिल्ली : पिछले साल दिल्ली मेट्रो के किराए में दो चरणों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, जो दोगुने से अधिक थी। डीएमआरसी के इस कदम ने मेट्रो रेल सेवा की स्थापना के उद्देश्य को नकार दिया, जो था लोगों को सस्ता, तेज और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रदान करना। इस नाजायज किराया वृद्धि ने पूरे दिल्ली में लाखों यात्रियों पर भारी बोझ डाल दिया है। उनमें से सबसे ज्यादा छात्र समुदाय प्रभावित हुआ है। किराया निर्धारण समिति अब स्वत:स्फूर्त ढंग से किराया हर साल बढ़ा देगी।

इस मेट्रो किराया वृद्धि के खिलाफ एआईडीएसओ की दिल्ली स्टेट कमेटी ने व्यापक अभियान चलाया। दिल्ली विश्वविद्यालय के 11 कॉलेजों, अम्बेडकर विश्वविद्यालय और प्रमुख मेट्रो स्टेशनों पर छात्रों के बीच एक हस्ताक्षर अभियान और जनमत संग्रह कार्यक्रम किया गया है। 94% छात्रों ने किराया वृद्धि को खारिज कर दिया और 99% छात्रों ने रियायती मेट्रो पास के लिए संगठन की मांग का समर्थन किया। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में 17 फरवरी को विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर मानव श्रृंखला बनाई गई। बड़ी संख्या में छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 20 फरवरी, 2018 को डीएमआरसी कार्यालय घेराव के साथ यह मानव श्रृंखला का लंबा अभियान सम्पन्न होगा। किराया वृद्धि तत्काल वापस लेने और छात्रों के लिए रियायती मेट्रो पास जारी करने की मांग की गई।

कॉमरेड विप्लव चक्रवर्ती लाल सलाम

18 जनवरी को कोलकाता जिला कमेटी एसयूसीआई(सी) के सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड विप्लव चक्रवर्ती का कोलकाता के बेहाला स्थित विद्यासागर अस्पताल में देहांत हो गया। वे 68 वर्ष के थे। सन् 2012 से ही वे एक असामान्य स्नायविक बीमारी 'सुपरा न्यूक्लियर प्लासी' से ग्रसित थे जिसमें स्नायु कोशिकाएं धीरे-धीरे सूखने लगती हैं। इसने न केवल उनका शारीरिक संतुलन बिगाड़ दिया था बल्कि हमेशा सक्रिय रहने वाले कॉमरेड को बिस्तर तक सीमित कर दिया था। अंतत: 18 जनवरी को इसके चलते उनकी मृत्यु हुई। लेकिन आखिरी क्षणों तक वे सचेत थे। हर तकलीफ को उन्होंने मुस्कुराते हुए झेला था। पार्टी हमेशा उनके विचारों में सर्वोपरि रही।

उनके निधन की खबर मिलते ही कोलकाता जिला सचिव मंडल सदस्यगण और राज्य कमेटी सदस्यगण श्रद्धांजलि देने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचे। हस्पताल से उनका शव घर लाया गया। बाद में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में लाया गया जहां वरिष्ठ पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. रंजीत धर ने पुष्पांजलि अर्पित की। पार्टी के महासचिव का. प्रभास घोष, पोलित ब्यूरो सदस्य कॉ. मानिक मुखर्जी और कॉ.असित भट्टाचार्य तथा केंद्रीय कमेटी सदस्य व पश्चिम बंगाल राज्य सचिव कॉ. सौमेन बोस की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई। अन्य राज्य कमेटी सदस्यों और जिला कमेटी सदस्यों, विभिन्न जन संगठनों और पार्टी के मुखपत्रों की ओर से भी श्रद्धांजलि दी गई।

कॉमरेड विप्लव चक्रवर्ती 1967-68 में कोलकाता के बेहाला क्षेत्र में स्थित एक पब्लिक लाइब्रेरी 'अध्ययन पाठागार' के माध्यम से किशोरावस्था में ही पार्टी के संपर्क में आए थे। तुरंत बाद ही महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से प्रभावित और गहराई से प्रेरित होकर उनकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं के आधार पर उन्होंने तब कम्युनिस्ट चरित्र हासिल करने का जोरदार संघर्ष चलाया था। इस प्रक्रिया में पार्टी द्वारा जो भी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई, उसको उन्होंने खुशी-खुशी और समर्पित भाव से निभाई और पार्टी नेतृत्व के सामने बेझिझक होकर अपने विचार और समस्याएं रखी। उनके खुले दिल वाले, मदद के लिए सदा तत्पर रहने वाले, सादे और सौम्य चरित्र ने उनको न केवल पश्चिम बगाल में बल्कि पश्चिम बंगाल के बाहर भी पार्टी में सबका प्यारा बना दिया था।

30 जनवरी को दक्षिण कोलकाता के आशुतोष कॉलेज हाल में कॉमरेड विप्लव चक्रवर्ती की स्मृति सभा आयोजित की गई। पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड रणजीत धर और कॉमरेड असित भट्टाचार्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड छाया मुखर्जी और कॉमरेड सौमेन बोस (सचिव, पश्चिम बंगाल राज्य कमेटी), सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड चितरंजन चक्रवर्ती और कॉमरेड अमिताभ चटर्जी की उपस्थिति में गंभीरता और मर्यादा के साथ सभा का संचालन किया गया। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं तथा कॉमरेड विप्लव चक्रवर्ती के परिवारजनों व मित्रों ने भारी मन से सभा में शिरकत की। सभा की अध्यक्षता कॉमरेड चितरंजन चक्रवर्ती ने की। कॉमरेड अमिताभ चटर्जी ने उनके समर्पित संघर्ष के बारे में बताया।

कॉ. विप्लव चक्रवर्ती लाल सलाम!

कॉमरेड राम आसरे मौर्य लाल सलाम

एसयूसीआई(सी) के उत्तर प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सदस्य, कॉमसोमोल के उ.प्र. राज्य संयोजक और एआईयूटीयूसी के पूर्वी उत्तर प्रदेश कमेटी के सचिव कॉमरेड राम आसरे मौर्य का देहान्त 30 जनवरी 2018 को हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनको ब्लड कैंसर हो गया था और मुंबई के टाटा अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे एक बहुत लोकप्रिय जननेता थे और क्रान्तिकारी आन्दोलन के बड़े अच्छे संगठनकर्ता थे। सर्वहारा के महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने 1980 के दशक में पार्टी में काम करना शुरू किया था। एआईडीएसओ और जौनपुर व उससे लगते इलाकों में पार्टी संगठन को भी विकसति करने में उन्होंने सराहनीय पहल कदमी की थी। बाद में, जब उन्होंने शिक्षक का पेशा अपनाया तब उन्होंने अपने छात्रों को क्रान्तिकारी आन्दोलन में शामिल कराने की कोशिश की। उन्हें बच्चों और छात्रों से विशेष लगाव था और वे स्वस्थ तन में स्वस्थ मन विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध थे। कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से मार्ग दर्शित होकर वे बच्चों के सामने बीते जमाने के महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानीयों के जीवन संघर्ष का वर्णन किया करते थे ताकि वे उनसे सीख लें और इस तरह उन्नत सर्वहारा क्रान्तिकारी विचारधारा से लैस हों।

उनका शव 1 फरवरी 2018 को उनके निवास स्थान अर्जुनपुर, जिला जौनपुर लाया गया। उनकी अंतिम यात्रा में छात्र, अध्यापक, हजारों क्षेत्रवासी व पार्टी कॉमरेड शामिल हुए और अश्रुपूरित नेत्रों से दिवंगत कॉमरेड को अंतिम विदाई दी। उनकी इस आकस्मिक मृत्यु से परिवार, पार्टी व शुभचिंतकों में गहरा शोक छा गया था।

कॉमरेड राम आसरे मौर्य की याद में एक शोक-सभा का आयोजन 7 फरवरी 2018 को प्राथमिक विद्यालय बहरीपुर, जौनपुर के प्रांगण में किया गया। इसकी अध्यक्षता पार्टी के जौनपुर जिला सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य ने की और संचालन कॉमरेड मिथिलेश कुमार मौर्य ने किया। सभा के मुख्य वक्ता कॉमरेड पुष्पेंद्र विश्वकर्मा (उत्तर प्रदेश राज्य सचिव) थे। सभा को कॉमरेड जगन्नाथ वर्मा (राज्य कार्यालय सचिव), कॉमरेड बेचन अली (प्रतापगढ़), कॉमरेड जयप्रकाश मौर्य (लखनऊ), कॉमरेड हीरालाल मौर्य, राज बहादुर मौर्य, महेंद्र कुमार मौर्य, राहुल मौर्य, रामदत्त मौर्य आदि ने संबोधित किया। पार्टी के उपरोक्त नेताओं के अलावा कई पार्टी कामरेड़ों, समर्थकों, हमदर्दों और छात्र-शिक्षकों ने दिवंगत कॉमरेड राम आसरे मौर्य को पुष्पांजलि अर्पित की। उनके निधन से पार्टी ने एक समर्पित संगठनकर्ता खो दिया।

कॉ. राम आसे मौर्य लाल सलाम!

कॉमरेड राम आसरे की शोक सभा

7 फरवरी 2018 को बहरीपुर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, कॉमरेड राम आसरे मौर्य की याद में शोक सभा

8 R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2018-20
Posting at New Delhi PSO on 7–8 and 22–23 of every month, Fortnightly , Date of Publication : February 20, 2018

सर्वहारा दृष्टिकोण

21 फरवरी से 7 मार्च 2018

तेलंगाना-आन्ध्र प्रदेश की अलग-अलग राज्य सांगठनिक कमेटियां गठित

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने 13 दिसम्बर, 2017 को हुई अपनी मीटिंग में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की राज्य सांगठनिक कमेटी को दो भागों में बांट कर अलग तेलंगाना राज्य सांगठनिक कमेटी और आन्ध्र प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी गठित करने का फैसला लिया। केन्द्रीय कमेटी ने कॉमरेड सीएच मुराहरी को तेलंगाना राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव के तौर पर काम करने और कॉमरेड बी. एस. अमरनाथ को आन्ध्र प्रदेश राज्य सांगठनिक कमेटी के सचिव के तौर पर काम करने के लिए भी चुना। केन्द्रीय कमेटी ने यह भी फैसला लिया कि पार्टी के स्टाफ मेम्बर कॉमरेड के. श्रीधर दोनों कमेटियों के काम काज की निगरानी किया करेंगे।

एसयूसीआई का तीसरा महासम्मेलन

एसयूसीआई(सी) की केन्द्रीय कमेटी ने 11 फरवरी 2018 को हुई अपनी मीटिंग में पार्टी का तीसरा महासम्मेलन करने का फैसला लिया है। संभावित समय नवंबर 2018 है। केन्द्रीय कमेटी ने पार्टी सदस्यता के नवीनीकरण सहित उसके लिए तमाम आवश्यक तैयारियाँ करने का निर्देश दिया है।

केन्द्रीय कमेटी ने पार्टी की स्टाफ मेम्बर और पश्चिमी बंगाल राज्य सचिव मण्डल के सदस्य कॉमरेड प्रनति भट्टाचार्या को केन्द्रीय कमेटी में लेने की भी घोषणा की।

तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई बस किराया वृद्धि का विरोध

चेन्नई : तमिलनाडु में एआईएडीएमके की सरकार ने 19 जनवरी को सभी प्रकार की बसों का किराया बढ़ा दिया है। इसके खिलाफ स्वत:स्फूर्त विक्षोभ फूट पड़ा है। छात्र कक्षाओं का बायकाट कर रहे हैं। एसयूसीआई (सी) की तमिलनाडू राज्य सांगठनिक कमेटी भी इसमें शामिल हो गई है। पार्टी ने मांग की है कि बस किराया वृद्धि को तमिलनाडु सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले।

बस किरायां वृद्धि के फैसले को वापस लेने की मांग पर वाम दलों द्वारा 22 जनवरी को चेन्नई जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए एसयूसीआई(सी) के राज्य सचिव कॉमरेड ए रंगस्वामी ने बस किराया बढ़ोतरी के खिलाफ संयुक्त आन्दोलन तेज करने का आह्वान किया।

एसयूसीआई (सी), सीपीआई (एम) और सीपीआई-एमएल (लिबरेशन) आदि वाम दलों ने संयुक्त रूप से 12 फरवरी को सचिवालय मार्च आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उसी शाम को रिहा कर दिया गया। इसी दिन मदुरई, सलेम,और तेनी में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गये।

त्रिपुरा में पांच सीटों पर चुनाव लड़ी एसयूसीआई(सी)

18 फरवरी को सम्पन्न त्रिपुरा राज्य विधानसभा चुनाव में पाँच सीटों पर एसयूसीआई(सी) के उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं।

उम्मीदवारों की सूची

क्र.	केंद्र	जिला	उम्मीदवार
1.	बारडोली	पश्चिम त्रिपुरा	कॉमरेड शिवानी भौमिक
2.	बनलपुर	पश्चिम त्रिपुरा	कॉमरेड शेफाली देबनाथ
3.	बधारघाट	पश्चिम त्रिपुरा	कॉमरेड मृदुलकांति
4.	धर्मनगर	पश्चिम त्रिपुरा	कॉमरेड संजय चौधरी
5.	मदरबाड़ी	गोमती	कॉमरेड धडुलाल डी

सबको रोजगार देने की मांग पर एआईडीवाईओ ने छेड़ा आन्दोलन

बेरोजगारी के विरोध में और सभी सक्षम लोगों को रोजगार देने की मांग पर एआईडीवाईओ ने देशभर में विभिन्न कार्यक्रम लेकर नये जोश के साथ एक जोरदार आन्दोलन छेड़ा है। एआईडीवाईओ ने एक करोड़ से ज्यादा जन हस्ताक्षर कराने का टारगेट लिया है। फरवरी मार्च महीनों में ब्लॉक स्तरीय प्रदर्शन और कानून भंग करने का भी निर्णय लिया है।

सबको रोजगार देने की मांग पर राजस्थान, कर्नाटक व हरियाणा में ऑल इण्डिया डीवाईओ के हस्ताक्षर अभियान (नीचे)

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."

Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com , sarvaharadrishtikon@yahoo.com

फोन न. : 011-25726631, 9868350503